

ग्रसाभारण

EXTRAORDINARY

भाग **II- खण्ड** 3--उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

तं• 172]

नई बिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1975/म्रायात 6, 1897

No. 172]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27 1975/ASADHA 6, 1897

इस भाग में भिन्न रुष्ट लंख्या वी जाती है जिससे कि यह झलग संनलन के कन में रक्ता का बने ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 27th June 1975

G.S.R. 361(E)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 359 of the Constitution, the President hereby declares that the right of any person (including a foreigner) to move any court for the enforcement of the rights conferred by article 14, article 21 and article 22 of the Constitution and all proceedings pending in any court for the enforcement of the abovementioned rights shall remain suspended for the period during which the Proclamations of Emergency made under clause (1) of article 352 of the Constitution on the 3rd December, 1971 and on the 25th June, 1975 are both in force.

This Order shall extend to the whole of the territory of India except the State of Jammu and Kashmir.

This Order shall be in addition to and not in derogation of any Order made before the date of this Order under clause (1) of article 359 of the Constitution.

[No. II/16013/1/75-S&P(D)II]

S. L. KHURANA, Secy.

गृह मंत्रालय

स्रादेश

नई बिल्ली, 27 जून, 1975

साठ काठ निरु 361(म्).—संविधान के भ्रमुच्छेद 359 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त गिक्सियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि संविधान के भ्रमुच्छेद 14, भ्रमुच्छेद 21 घौर भ्रमुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त ग्रधिकारों के प्रवर्तन के लिये किसी भी व्यक्ति (जिसमें विदेशी शामिल हैं) का न्यायालय में जाने का श्रधिकार भ्रीर उक्त श्रधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में विचारणाधीन सभी कार्यवाहियां, उस भ्रवधि तक निरस्त रहेंगी जब तक कि संविधान के भ्रमुच्छेद 352 के खंड (1) के भ्रधीन, 3 दिसम्बर, 1971 भ्रीर 25 जून, 1975 को की गई भ्रापातकालीन स्थित की दोनों उद्घोषणाएं प्रवृत्त है।

यह ब्रादेश जम्म व कश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत के समस्त क्षेत्रों में लागू होगा।

यह प्रादेश संविधान के प्रनुच्छेद 359 के खंड (1) के प्रधीन इस प्रादेश की तारीख से पहले बनाए गये किसी प्रादेश का परिवर्धन होगा न कि प्रपक्ष ।

[सं॰ II/16013/1/75-एस एन्ड पी (डी)II] एस॰ एल॰ खुराना, सन्विव ।